वर्ष-16 - अंक 100
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर साप्ताहिक
बुधवार, 12 अगस्त 2026

RNI.No. (UHIN/2009/34814)

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

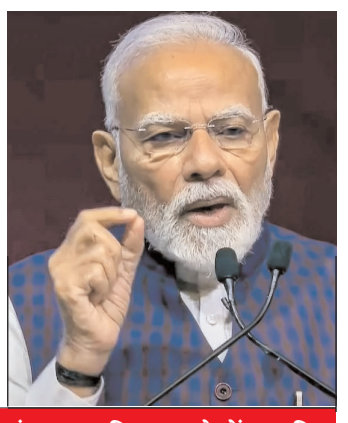

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाज़ियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

डिजिटल भारत और साइबर अपराध..... 2 | जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता.. 3 | थारू विकास परियोजना को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का हब बनाने की कवायद 04

जेएसएससी जेई पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई

परीक्षा एजेंसी के मैनेजर समेत छह गिरफ्तार

रांची(एजेंसी)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 में आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में परीक्षा संचालन एजेंसी के मैनेजर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एजेंसी के निदेशक सह मैनेजर अरुण कुमार को एसआईटी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच के अनुसार, जेएसएससी की ओर से तीन जुलाई 2022 को 1279 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र और उसके उत्तर कथित तौर पर अभ्यर्थियों तक पहुंचने की जानकारी सामने आई थी। मामले की जांच में परीक्षा संचालन एजेंसी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई। एसआईटी ने दिल्ली स्थित बायनसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की परीक्षा एजेंसी के मैनेजर कृष्ण कुमार तथा पूर्व अभ्यर्थियों रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार और दीपक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। इनके साथ फरार चल रहे एजेंसी के निदेशक सह मैनेजर अरुण कुमार को मुंबई से पकड़ा गया। अरुण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने मामले की जांच और तेज कर दी है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र किस स्तर से

लीक हुआ, इसे किसने हासिल किया और अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र व उत्तर पहुंचाने में किन लोगों की भूमिका रही। जांच में कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाने की बात भी सामने आई है। एसआईटी परीक्षा संचालन एजेंसी से जुड़े अन्य लोगों और पेपर लीक के पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। पेपर लीक मामले में इससे पहले भी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब परीक्षा संचालन एजेंसी के निदेशक की गिरफ्तारी को जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। एसआईटी अरुण कुमार से पूछताछ के जरिए मामले में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद जेएसएससी ने तीन जुलाई 2022 को आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अब नई गिरफ्तारियों के बाद एसआईटी के सामने पेपर लीक की पूरी श्रृंखला और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका उजागर करने की चुनौती है।

पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, बोले- 'जो खेलेगा, वो खिलेगा'

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और इस मुलाकात को यादगार बताया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान उनके संघर्ष, अभ्यास और प्रतियोगिता के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि युवाओं को अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास की सीख भी देते हैं। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक माध्यम पर भारतीय दल के साथ एक रील साझा की। इसमें प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। रील के साथ उन्होंने खेलों को लेकर प्रेरक संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जो खेलेगा, वो खिलेगा। हमेशा भारत के लिए उत्साह बढ़ाएं।' उनके इस संदेश को खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026

में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और नौ कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में पिछले संस्करणों की तुलना में प्रतियोगिताओं की संख्या कम थी। कई ऐसे खेल भी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थे, जिनमें भारत पारंपरिक रूप से मजबूत माना जाता है। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया और देश के खाते में 39 पदक जोड़े। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल भारतीय जूडो के लिए विशेष रहे। भारत ने पहली बार एक ही राष्ट्रमंडल खेल में जूडो में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और देश की पदक संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जूडो में मिली सफलता को भारतीय खेलों में नई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के युवा खिलाड़ियों को इस खेल में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं, तेजस्विन शंकर ने पुरुषों के डेकाथलॉन में कांस्य पदक हासिल किया। डेकाथलॉन जैसी कठिन बहु-स्पर्धा में पदक जीतना भारतीय एथलेटिक्स के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है।

भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में देश की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाया। मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। भारतीय मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतकर देश को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी में मिले पदकों ने भारतीय दल को पदक तालिका में मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खेल जगत में भी सराहना हुई। भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा खिलाड़ियों ने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वहीं, पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। पैरा खिलाड़ियों की सफलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और भारत की पदक संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात को भारतीय खिलाड़ियों ने विशेष अवसर बताया। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ प्रतियोगिता से जुड़े अनुभव साझा किए और बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गौरव का विषय रहा।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए खेलों में निरंतर मेहनत करने और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का संदेश दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की 39 पदकों की उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से मिलना उनके उत्साह को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

20 अगस्त तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को राहत, स्टेडियम ड्यूटी भी रद्द

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और कश्मीरी पंडित एवं अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। श्रीनगर में कार्यरत पीएम पैकेज, गैर-पीएम पैकेज और प्रवासी कर्मचारियों को 20 अगस्त 2026 तक कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति से राहत दी गई है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेडियम में आयोजित होने वाले आधिकारिक समारोह की ड्यूटी से भी इन कर्मचारियों को अलग रखा गया है। श्रीनगर में करीब 2,800 कर्मचारियों को यह राहत दिए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, संबंधित अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को तत्काल राहत मिल सके। बताया गया है कि यह फैसला श्रीनगर एम्प्लॉइज कलेक्टिव की ओर से जिला उपायुक्त अक्षय लबरू को भेजे गए पत्र के बाद लिया गया। कर्मचारी संगठन ने घाटी में पूर्व में हुई लक्षित हत्याओं का हवाला देते हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों में बनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से प्रशासन को अवगत कराया था। कर्मचारी संघ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्टेडियम ड्यूटी से छूट देने के साथ ही कार्यालय में भौतिक उपस्थिति से अस्थायी राहत देने की मांग की थी। संगठन की ओर से सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को 25 अगस्त तक कार्यालय आने से छूट देने का अनुरोध किया गया था।

संक्षिप्त ख़बरें

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 13 से 16 अगस्त 2026 तक राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम लागू रहेंगे। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और ट्रेनों में सघन जांच के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। यात्रियों और उनके सामान की जांच की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में आरपीएफ, जीआरपी और पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलने पर तत्काल सुरक्षा कर्मियों को सूचना देने को कहा गया है। रेलवे ने बताया कि सुरक्षा जांच बढ़ाए जाने के कारण स्टेशनों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक समय लग सकता है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित समय से काफी पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि सुरक्षा जांच के कारण ट्रेन छूटने की स्थिति न बने।

2,000 करोड़ के चिटफंड घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। करीब 2,000 करोड़ रुपये के बहु-राज्यीय चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने विशाखापत्तनम और हैदराबाद में पांच परिसरों पर छापेमारी कर 1.01 करोड़ रुपये नकद, छह महंगी लग्जरी कारें और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ने 182 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी जारी किए हैं। ईडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 5 अगस्त को वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूबीईपीएल) और उसके निदेशकों से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई विशाखापत्तनम और हैदराबाद में की गई। ईडी के अनुसार, पूर्व आंध्र प्रदेश विधायक मल्ला विलाया प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला और अन्य से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को विभिन्न चल और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली।

संकल्प लेकर आगे बढ़ें युवा, लक्ष्य से न भटकें': मुख्यमंत्री धामी

देहरादून(एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से ढाई लाख से अधिक युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। युवा अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए देश और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। कोई उद्यमी बनेगा तो कोई डॉक्टर, किसान, शिक्षक या अन्य क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा तकनीक और

नई सोच के दौर में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि नई पीढ़ी की सोच को समझना और उसे सही दिशा देना जरूरी है। युवाओं को परिवहन, स्वच्छता और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भी नए विचारों के साथ आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिकागो में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी विचारधारा ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य से पहले संकल्प लेने की परंपरा है और यही संकल्प आगे चलकर सिद्धि का कारण बनता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें भी जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां बार-बार विकल्प बदलने से लक्ष्य से भटकने की संभावना रहती है। इसलिए युवाओं को अपने लक्ष्य को मिशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यही युवा उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के सामने नशे की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताई। एक विद्यार्थी ने कहा कि उसके मोहल्ले में शराब की दुकान है। ऐसे में नशे पर रोक कैसे लगेगी। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर स्कूलों के आसपास भी नशीले पदार्थों की बिक्री होती है और ड्रग्स माफिया युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा दिव्या ने नशे की दुकानों को बंद कराने की मांग की। वहीं साहिना ने पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की बिक्री और सामाजिक आयोजनों में शराब परोसे जाने का मुद्दा उठाते हुए उत्तराखंड में शराब पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की।

पान मसाला कंपनियों को बड़ा झटका

प्लास्टिक पैकेजिंग पर एफएसएसएआई ने कसा शिकंजा

नई दिल्ली। पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नियमों को और सख्त कर दिया है। नए संशोधन के तहत प्लास्टिक आधारित तथा प्लास्टिक से लैमिनेट की गई पैकेजिंग को पान मसाला के लिए अनुमत या निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री की सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे पान मसाला बनाने और पैक करने वाली कंपनियों को अपनी पैकेजिंग व्यवस्था में बदलाव करना पड़ सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार पान मसाला की पैकेजिंग के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक-लैमिनेटेड सामग्री को अब पान मसाला के लिए निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। एफएसएसएआई के इस संशोधन का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो पान मसाला उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक आधारित सामग्री का इस्तेमाल करती हैं। कंपनियों को अब पैकेजिंग के लिए निर्धारित और अनुमत सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। संशोधित नियमों के बाद पान मसाला उत्पादों की पैकेजिंग करने वाली कंपनियों को नियामकीय मानकों के अनुरूप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियां कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। एफएसएसएआई का यह कदम खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग से जुड़े मानकों को स्पष्ट और सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब बांग्लादेश की पटरियों पर दौड़ेंगे भारत में बने एलएचबी कोच, पहली रैक तैयार

कपूरथला(एजेंसी)। भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता और स्वदेशी कोच निर्माण की विशेषज्ञता को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 20 एलएचबी कोच वाली पहली रैक तैयार कर ली है। बांग्लादेश रेलवे की जरूरतों के अनुरूप इन कोचों में कई नए डिजाइन और तकनीकी बदलाव किए गए हैं। आरसीएफ के अनुसार, कुछ डिजाइन विशेषताएं पहली बार एलएचबी कोच में शामिल की गई हैं। तैयार की गई पहली रैक में कुल 20 एलएचबी ब्रॉडगेज यात्री कोच हैं। इनमें तीन एसी स्लीपर, तीन एसी चेयर कार, 12 गैर-वातानुकूलित चेयर कार और दो पावर कोच शामिल हैं। बांग्लादेश रेलवे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोचों की डिजाइन और सुविधाओं में बदलाव किया गया है। इन कोचों में यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ बांग्लादेश रेलवे के परिचालन मानकों को ध्यान में रखा गया है। आरसीएफ का कहना है कि इस परियोजना के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग और कोच निर्माण क्षमता का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हुआ है।

एफसीआरए बिल को लेकर टकराव तेज, जेपीसी के विकल्प पर सरकार का मंथन

नई दिल्ली(एजेंसी)। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक, 2026 को लेकर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और द्रमुक (डीएमके) समेत विपक्षी दल जहां विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में बुधवार को लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधेयक को लेकर मंगलवार को राज्यसभा

की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी चर्चा हुई। हालांकि FCRA विधेयक बैठक के निर्धारित एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के सदस्यों ने सरकार से पूछा कि इस पर सदन में चर्चा कब कराई जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया कि उचित समय आने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस और टीएमसी ने FCRA संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की है। द्रमुक भी विधेयक को वापस लेने के पक्ष में है। वहीं, बीजू जनता दल (बीजेडी) समेत कुछ दलों का मानना है कि विधेयक को विस्तृत जांच और सभी पक्षों पर विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रस्तावित संशोधनों के कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों और ईसाई गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाली वैध विदेशी सहायता को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि विदेशी चंदे से संचालित सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक गतिविधियों पर नए प्रावधानों का असर पड़ सकता है। FCRA संशोधन विधेयक, 2026 को इसी वर्ष 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मिलने वाले विदेशी अंशदान की निगरानी और नियमन की व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान ऐसी प्राधिकरण व्यवस्था बनाने से जुड़ा है।

यूपी में करदाताओं को बड़ी राहत

संपी कर बकाया चुकाने के लिए ओटीएस योजना लागू

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लंबे समय से संपत्ति कर के बकाये में फंसे करदाताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर यानी गृहकर, जलकर और सीवरकर की प्रभावी वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल और व्यावहारिक तरीके से निस्तारण कराने के

साथ करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना तथा कर संबंधी न्यायालयीय विवादों में कमी लाना है। एकमुश्त समाधान योजना की अवधि चार माह निर्धारित की गई है। योजना का क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। नगरीय निकायों की ओर से 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच सभी संबंधित करदाताओं और हितधारकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र करदाता योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकें और लंबे समय से लंबित अपने कर बकाये का निस्तारण करा सकें। करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने ओटीएस के तहत बकाया संपत्ति कर के भुगतान की सुविधा को आसान बनाया है। योजना के अंतर्गत करदाता बकाया धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में कर सकेंगे। योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर करदाता को कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। इसके बाद शेष दो-तिहाई धनराशि अगले दो माह में दो मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन माह की अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से उन करदाताओं को भी राहत मिलेगी, जो एकमुश्त बड़ी राशि जमा करने में असमर्थ हैं। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पीएम मोदी का वीडियो संदेश, बोले- 'हर घर तिरंगा' को बनाएं देश का उत्सव

नई दिल्ली(एजेंसी)। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान को केवल तिरंगा फहराने तक सीमित न रखते हुए हर घर में एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, 'हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आइए, हम हर घर में तिरंगा फहराएं।' उन्होंने देशवासियों से 15 अगस्त को गर्व और सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने तथा स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अगस्त महीने में देशभर

में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों में तिरंगे के प्रति सम्मान, गौरव और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में शामिल होकर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।

संपादकीय

डिजिटल भारत और साइबर अपराध

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज बैंकिंग से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सरकारी सेवाओं और व्यक्तिगत संवाद तक लगभग हर क्षेत्र इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है। डिजिटल इंडिया अभियान ने करोड़ों लोगों को तकनीक से जोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का दायरा और जटिलता भी तेजी से बढ़ी है। हर दिन ऑनलाइन ठगी, बैंक खाते खाली होने, फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया हैकिंग और डेटा लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे कानून और जांच एजेंसियां साइबर अपराधियों की गति के साथ कदम मिला पा रही हैं, या अपराधी कानून से आगे निकल चुके हैं? डिजिटल क्रांति ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले अपराध किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित होते थे, अब एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी राज्य के नागरिक को कुछ ही मिनटों में अपना शिकार बना सकता है। अपराधी नकली वेबसाइट, फर्जी मोबाइल ऐप, एआई आधारित आवाज की नकल, डीपफेक वीडियो और सोशल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं। कई मामलों में पीड़ित को तब तक पता नहीं चलता, जब तक उसके खाते से लाखों रुपये गायब नहीं हो जाते। भारत में साइबर अपराधों के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधान डिजिटल अपराधों पर कार्रवाई की अनुमति देते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन 1930, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और डिजिटल भुगतान सुरक्षा से जुड़े कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से हजारों मामलों में धनराशि फ्रीज कर पीड़ितों को राहत भी मिली है। फिर भी वास्तविक चुनौती यह है कि अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कानून से कहीं अधिक तेज़ी से कर रहे हैं। कानून बनने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में समय लगता है, जबकि साइबर अपराधी कुछ ही दिनों में नए तरीके विकसित कर लेते हैं। एआई ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। आज किसी की आवाज की हूबहू नकल कर फोन किया जा सकता है, किसी का नकली वीडियो तैयार किया जा सकता है और फर्जी पहचान बनाकर आर्थिक अपराध किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में पारंपरिक जांच प्रणाली कई बार अपर्याप्त साबित होती है। साइबर अपराध की एक बड़ी समस्या इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति भी है। अनेक गिरोह भारत के बाहर से संचालित होते हैं। उनके सर्वर दूसरे देशों में होते हैं और धन कई देशों के बैंक खातों या क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य और कानूनी प्रक्रियाएं जांच को लंबा और जटिल बना देती हैं। अपराधी इसी देरी का लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर नागरिकों में डिजिटल जागरूकता की कमी भी अपराधियों की सफलता का बड़ा कारण है। आज भी अनेक लोग अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ओटीपी साझा कर देते हैं, नकली निवेश योजनाओं के झांसे में आ जाते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं। तकनीकी सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आवश्यक डिजिटल साक्षरता भी है। यदि नागरिक सतर्क हों तो बड़ी संख्या में साइबर अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। भारत को अब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले कानूनों को तकनीकी बदलावों के अनुरूप लगातार अद्यतन करना होगा। एआई आधारित अपराध, डीपफेक, डेटा चोरी और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों के लिए स्पष्ट और प्रभावी कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं। दूसरा, पुलिस और जांच एजेंसियों को आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक, साइबर विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाना होगा। तीसरा, राज्यों के बीच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को और तेज़ करना होगा। बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान कंपनियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। संदिग्ध लेनदेन की तुरंत पहचान, मजबूत सत्यापन प्रणाली, फर्जी खातों पर त्वरित कार्रवाई और उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी चेतावनी देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। निजी क्षेत्र और सरकार के बीच समन्वय जितना मजबूत होगा, साइबर अपराध पर नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा। शिक्षा व्यवस्था में भी डिजिटल सुरक्षा को शामिल करने का समय आ गया है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर साइबर सुरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सड़क सुरक्षा के नियम सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार डिजिटल सुरक्षा के नियम भी नागरिक जीवन का हिस्सा बनने चाहिए। डिजिटल भारत की सफलता केवल इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि नागरिक डिजिटल दुनिया में कितने सुरक्षित हैं। यदि कानून, तकनीक, प्रशासन और समाज मिलकर साइबर अपराध के विरुद्ध मजबूत व्यवस्था विकसित नहीं करते, तो डिजिटल प्रगति का लाभ अपराधियों को अधिक मिलेगा और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करेंगे।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

मेष-मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त लाभ के संकेत हैं।

वृषभ-वृषभ राशि वालों के लिए आज परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

मिथुन-मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नए अवसरों का दिन है। व्यापार और नौकरी में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। अनावश्यक यात्राओं से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

कर्क-कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यदि किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी।

सिंह-सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और अधिकार मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और परिवार में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है।

कन्या-कन्या राशि वालों को आज परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन विवाद से बचें। भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा। यात्रा करते समय आवश्यक सावधानी बरतें।

तुला-तुला राशि के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। कला, साहित्य, शिक्षा और सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

वृश्चिक-वृश्चिक राशि वालों को आज संपत्ति और वित्तीय मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ सकता है। धैर्य और संयम से लिया गया निर्णय आपके हित में रहेगा।

धनु-धनु राशि के जातकों के लिए आज मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता की सराहना होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।

मकर-मकर राशि वालों के लिए आज का दिन परिश्रम और उपलब्धियों का संतुलन लेकर आएगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

कुंभ-कुंभ राशि के जातकों के लिए आज ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलेगा। आपकी सलाह से दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा, प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मीन-मीन राशि वालों को आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत पूरी तैयारी के साथ करनी चाहिए। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। लंबी दूरी की यात्रा यदि टाली जा सके तो बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी साबित होंगे।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से गरीबों को मिल रहा पक्का आशियाना

(आदर अदीब पावेल बन्धु)
जिला सूचना अधिकारी

आवास केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार भी होता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना घर होना आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने मुयमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जो किसी कारणवश अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं ले सके।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, आवासहीन एवं कच्चे मकानों में निवास कर रहे परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। आवास केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार भी होता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना घर होना आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जो किसी कारणवश अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं ले सके। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहे हैं, जो वर्षों से कच्चे मकानों, झोपड़ियों अथवा अस्थायी आश्रयों में जीवन यापन करते आए हैं। बरसात, गर्मी, सर्दी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कच्चे घरों की असुरक्षा के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन विशेष रूप से प्रभावित होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीबों के जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान लाने की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में सामने आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जो आवासहीन हैं या जर्जर एवं कच्चे मकानों में रह रहे हैं। साथ ही, ऐसे पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या अन्य योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें इस योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे और प्रत्येक जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास मिल सके। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता चरणबद्ध तरीके से किस्तों में दी जाती है, जिससे निर्माण कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। आमतौर पर प्रथम किस्त निर्माण प्रारंभ करने हेतु, द्वितीय किस्त निर्माण की प्रगति के आधार पर तथा अंतिम किस्त निर्माण पूर्ण होने पर दी जाती है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में आवास निर्माण में ही हो। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विशेष रूप से गरीब, असहाय, वंचित, निराश्रित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, महिला मुखिया परिवारों तथा अन्य जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देती है। योजना में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भावना निहित है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे ।लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान की जाती है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सत्यापन के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। पक्का घर मिलने से गरीब परिवारों को सुरक्षित वातावरण मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर पाते हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और बुजुर्गों को भी आरामदायक जीवन मिलता है। पक्का आवास गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सम्मान का भी आधार बनता है। पहले जो परिवार झोपड़ी या जर्जर कच्चे घरों में रहते थे, उन्हें समाज में अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब पक्का घर मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मजबूत होती है। यह योजना गरीबों के जीवन में केवल भौतिक परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव लाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई मामलों में आवास महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलता है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में उनकी निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पक्के घरों में स्वच्छ वातावरण, बेहतर वेंटिलेशन और सुरक्षित संरचना होने के कारण बीमारियों का खतरा कम होता है। साथ ही स्वच्छता से जुड़े अन्य प्रयासों को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सुधार में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। निर्माण कार्य में मजदूरों, राजमिस्त्रियों, कारीगरों और निर्माण सामग्री की मांग बढ़ती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार यह योजना रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी योगदान देती है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को आवास सुविधा उपलब्ध हो और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता समाप्त हो। इस दिशा में निरंतर कार्य करते हुए बड़ी संख्या में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। योजना के माध्यम से हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन में बदलाव लाया गया है। इससे न केवल उनकी रहने की स्थिति सुधरी है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। यह योजना ग्रामीण विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध हुई है। हालांकि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान, निर्माण कार्य की समयबद्धता, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच औरजागरूकता का अभाव। लेकिन सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तकनीकी साधनों, निगरानी तंत्र और प्रशासनिक सक्रियता के माध्यम से योजना को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वास्तव में गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन की नींव रखने वाली योजना है। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना का प्रतीक है। जब किसी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो वह केवल दीवारें और छत नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य, नई आशा और आत्मसम्मान का आधार बनती है। ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवासीय सुरक्षा मिलने के बाद गरीब परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के निर्माण को बल मिलता है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प निहित है। यह योजना गरीबों के सपनों को साकार करने, सामाजिक असमानता को कम करने और समृद्ध ग्रामीण उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीबों के जीवन में आशा, सुरक्षा और सम्मान का संचार करने वाली एक प्रभावशाली योजना है। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के समग्र विकास की आधारशिला है। आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से और अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित कर 'हर गरीब को आवास' के लक्ष्य को और अधिक मजबूती से साकार किया जा सकेगा।

जनपद गाजियाबाद में अंत्योदय और समावेशी विकास से साकार होता दिव्यांगजन सशक्तिकरण

प्रदेश सरकार के सर्वांगीण और समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। 'सहानुभूति नहीं, अधिकार एवं अवसर' के प्रगतिशील विचार को अपनाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसे बाधा-मुक्त और सुगम वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जहां प्रत्येक दिव्यांग नागरिक गरिमा, स्वाभिमान और पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ समाज की मुख्यधारा में अपना योगदान दे सके। इस दिशा में प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी प्राथमिकताओं और पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी संकल्पना को साकार करते हुए जनपद गाजियाबाद ने 'सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय' के मूलभूत मंत्र को अपनाते हुए दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों से परंपरागत दयाभाव की अवधारणा को पीछे छोड़ते हुए दिव्यांगजनों को पूर्ण आत्मसम्मान और स्वावलंबन युक्त जीवन प्रदान करने का एक सुदृढ़ मॉडल आकार ले चुका है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में लागू की गई इस रणनीतिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं के परस्पर समन्वय से अब तक जनपद में दस हजार से अधिक दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड और प्रामाणिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित क्रियान्वयन के चलते जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच अत्यंत सुगम बन गई है। प्रदेश सरकार की सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इस आर्थिक संबल से जनपद के हजारों लाभार्थी अपने दैनिक जीवन-यापन को सुगमता से संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए किन्तु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विशेष मानवीय संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भी एक सम्मानजनक उच्चीकृत पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इस विशेष आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का समाज में उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें एक गरिमामय जीवन-यापन का अधिकार प्रदान करना है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त दिव्यांगजनों की भौतिक सुगमता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन एवं वितरण शिविरों के माध्यम से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र और दृष्टिबाधितों के लिए आधुनिक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन उपकरणों के वितरण ने दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन को बेहद सरल और सुलभ बना दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की उपलब्धता से जनपद गाजियाबाद के दिव्यांग युवाओं, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों की अपने कार्यस्थल एवं शिक्षण संस्थानों तक पहुँच सुगम हुई है, जिससे उनकी उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार के परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों एवं उनके एक सहयोगी के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा ने उनकी गतिशीलता को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। शिक्षा और कौशल विकास को सशक्तिकरण का मूलमंत्र मानते हुए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू की है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। जनपद गाजियाबाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है। विशिष्ट शिक्षण केंद्रों के माध्यम से श्रवण, वाक एवं अन्य शारीरिक भिन्नताओं से प्रभावित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित स्पीच थेरेपी, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। इन समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप जिले के विशेष बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर निरंतर पदक व सम्मान अर्जित कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और आजीविका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद गाजियाबाद में बहुआयामी स्वरोजगार एवं रोजगार मॉडल लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई सचल व्यावसायिक इकाइयों के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर व्यापार संचालित करने के सुरक्षित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह कदम उन्हें सीधे तौर पर आजीविका से जोड़ने में अत्यधिक कारगर सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन द्वारा निजी प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर दिव्यांग युवाओं की योग्यता एवं कौशल के अनुसार उन्हें सम्मानजनक नौकरियों में समायोजित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की सूक्ष्म ऋण सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन रोजगारोन्मुख प्रयासों से सैकड़ों दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों के मुख्य संबल के रूप में उभरे हैं।

दिव्यांगजनों के सामाजिक एकीकरण और पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के ध्येय से लागू शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रदेश सरकार की एक विशिष्ट और संवेदनशील पहल है। इसके तहत विवाह करने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन धनराशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। यह योजना दिव्यांगजनों के प्रति व्याप्त सामाजिक भ्रांतियों और उपेक्षात्मक सोच को समाप्त करने में एक मील का पत्थर साबित हुई है। आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान भी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर एक संवेदनशील एवं जवाबदेह पैरवी तंत्र कार्यरत है। परिवहन एवं रेल यात्रा रियायत पत्रों के निर्गमन और विभागीय बाधाओं के त्वरित निवारण हेतु जनपद गाजियाबाद में नियमित अंतराल पर सुगम समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश सरकार के अभियानों के तहत सभी प्रमुख प्रशासकीय भवनों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों को रैंप तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से पूर्णतः बाधारहित बनाया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में प्राप्त इस असाधारण सफलता का मुख्य आधार जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता और निरंतर अनुश्रवण रहा है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों का सुचारू क्रियान्वयन यह स्पष्ट करता है कि यदि दिव्यांगजनों को उचित अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो वे किसी पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ बन सकते हैं। भविष्य की कार्ययोजनाओं को रेखांकित करते हुए जनपद गाजियाबाद में शिक्षा का आधुनिकीकरण, उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोग तथा पूर्णतया बाधारहित अवसंरचना के निर्माण की दिशा में प्रयास और भी तेज किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की यह दृढ़ प्रतिबद्धता है कि आगामी समय में आधुनिक तकनीक और नवाचारों का वृहद उपयोग कर प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे समावेशी विकास और उन्नत राष्ट्र की संकल्पना को निरंतर गति मिल सके।

सूचनाधिकारी जनपद गाज़ियाबाद/
डॉ0 सीमा गुप्ता (से0नि0 सहा0निदे0)

प्रोसेस्ड भोजन और सुस्त जीवनशैली बढ़ा रहे स्वास्थ्य संकटः विशेषज्ञ

बदलती खान-पान की आदतें, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन और शारीरिक गतिविधियों में लगातार कमी भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं एआईजी हॉस्पिटल्स के सेंटर फॉर ओबेसिटी एंड मेटाबोलिक थेरेपी के निदेशक डॉ. राकेश कलापाला ने चेतावनी दी है कि मोटापे को केवल बढ़ते वजन के रूप में नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली जटिल मेटाबोलिक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आईएएनएस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में डॉ. कलापाला ने कहा कि आज के समय में अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन, रिफाइंड शुगर, अधिक कार्बोहाइड्रेट और खराब वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ तेजी से लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं। यही कारण है कि मोटापा, फैटी लिवर, मधुमेह और अन्य मेटाबोलिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रोसेस्ड फूड भूख और खाने की इच्छा को और बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। इनमें प्रोटीन की कमी और अस्वास्थ्यकर वसा की अधिक मात्रा शरीर के मेटाबोलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। डॉ. कलापाला ने कहा कि आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी फैटी लिवर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जो न तो शराब का सेवन करते हैं और न ही मांसाहार करते हैं। इसके पीछे बदलती जीवनशैली, तनाव और असंतुलित खान-पान प्रमुख कारण हैं। उन्होंने बताया कि फैटी लिवर लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में विकसित होता रहता है। अधिकांश मामलों में इसका पता अल्ट्रासाउंड या लिवर फंक्शन टेस्ट के दौरान चलता है। जब तक बीमारी सामने आती है, तब तक लिवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। विशेषज्ञ के अनुसार, अत्यधिक मानसिक तनाव और घंटों तक बैठे रहने की आदत भी मेटाबोलिक बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि तनाव के कारण लोग अधिक भोजन करने लगते हैं और शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने सलाह दी कि हर 30 से 60 मिनट के बीच कम से कम एक-दो मिनट तक टहलना चाहिए, ताकि लंबे समय तक बैठे रहने के दुष्प्रभाव कम किए जा सकें। डॉ. कलापाला ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में बच्चों में मोटापे की दर 15 से 18 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में मोटापे की शुरुआत गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। यदि गर्भवती महिला का वजन अधिक होता है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसके अलावा पढ़ाई का बढ़ता दबाव, खेलकूद की कमी और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। डॉ. कलापाला ने गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक एंटासिड दवाओं के सेवन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन दवाओं का अनियंत्रित उपयोग हड्डियों और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है तथा कुछ शोधों में इसे पेट के कैंसर के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पेट से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और तब तक इलाज नहीं कराते, जब तक गंभीर लक्षण सामने नहीं आ जाते। इससे कोलोन पॉलीप्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। डॉ. कलापाला ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अधिक वजन घटाना जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल वजन का केवल 10 प्रतिशत भी कम कर लेता है, तो इससे उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस, प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर चर्चा की। उन्होंने विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सुझावों और जनअपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' के माध्यम से प्रयागराज एवं आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। 'जनता दर्शन' में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। श्री मौर्य ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अधिकारियों को शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ उनका समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री मौर्य ने कहा कि 'जनता दर्शन' सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना जाता है और उनकी वास्तविक स्थिति को समझकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से प्रभावी समाधान कराया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने और उनके समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के साथ जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

कम्पीटेंसी मैपिंग फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग पर तकनीकी व्याख्यान आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील कार्य परिवेश में किसी भी संगठन की सफलता उसके मानव संसाधनों की दक्षता, क्षमता एवं व्यक्तित्व विकास पर निर्भर करती है। कम्पीटेंसी मैपिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ज्ञान , कौशल , व्यवहार तथा कार्यकुशलता का मूल्यांकन कर उसे उपयुक्त दायित्वों एवं नेतृत्व भूमिकाओं के लिए विकसित किया जाता है। वहीं पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग व्यक्तित्व की विशेषताओं, व्यवहार शैली, संप्रेषण क्षमता एवं नेतृत्व गुणों का विश्लेषण कर व्यक्तिगत एवं संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विषय का महत्व उद्योग, शिक्षा, प्रशासन एवं प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता इं. वी.पी. सिंह, चेयरमैन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता एवं प्रभावी व्यक्तित्व का विकास प्रत्येक अभियंता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कम्पीटेंसी मैपिंग एवं पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के माध्यम से अभियंताओं एवं पेशेवरों की कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता तथा संगठनात्मक विकास को नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने मुख्य वक्ता के व्याख्यान की सराहना करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसे समसामयिक एवं ज्ञानवर्धक तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करती रहेगी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में इं. एम.एम. खान, निदेशक, ProLead Consultancy & Training Group, पूर्व मुख्य अभियंता, Renusagar Power Division, Hindalco (Aditya Birla Group) एवं पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर, NASH Engineering Group, Dubai (UAE) ने अपने व्याख्यान में Competency Mapping की अवधारणा, उसके विभिन्न आयामों, संगठनात्मक विकास में उसकी भूमिका तथा Personality Profiling के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसी भी संगठन की दीर्घकालिक सफलता उसके कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता के साथ-साथ उनके व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता एवं टीम भावना पर निर्भर करती है। उन्होंने विभिन्न उद्योगों के व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझाया कि उचित Competency Mapping एवं Personality Profiling से कर्मचारियों की कार्यक्षमता, संगठनात्मक संस्कृति तथा नेतृत्व विकास को प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के संयोजक इं. राजेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऐसे व्याख्यान अभियंताओं, प्रबंधकों, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं तथा उन्हें आधुनिक औद्योगिक एवं प्रबंधकीय आवश्यकताओं से परिचित कराते हैं।

नाविकों के सम्मान और कल्याण को समर्पित रही 'नाविक मान सम्मान संगोष्ठी'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में समुद्री क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार को गति देने वाले नाविकों के योगदान, परिश्रम और समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से वीआर मैरिटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 'नाविक मान सम्मान संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नाविकों, समुद्री उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिकारियों और समुद्री समुदाय के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम होटल सैवी ग्रैंड, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य समुद्र के अनदेखे नायकों के योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ नाविकों के कल्याण, सुरक्षा, रोजगार के अवसरों और उज्ज्वल भविष्य को लेकर सार्थक संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणास्रोत कैप्टन संजय पराशर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सोनिका पराशर, निदेशक रहे। उनकी पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नाविकों के समर्पण और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया। संगोष्ठी में समुद्री क्षेत्र में रोजगार और करियर की संभावनाओं, नाविकों के कल्याण, कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समुद्र की कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए देश और दुनिया के व्यापार को निरंतर गति देने वाले नाविक वास्तव में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। उनके योगदान को सम्मान और उचित सुविधाएं मिलना आवश्यक है। कार्यक्रम में कैप्टन संजय प्रशार, किशोर पति, भर्ती विभागाध्यक्ष तथा नेहा कुमारी, लखनऊ शाखा प्रभारी सहित समुद्री क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधि एवं प्रतिभागी मौजूद रहे। संगोष्ठी के माध्यम से 'नाविक का सम्मान, समृद्ध भारत का अभियान' का संदेश दिया गया। आयोजकों ने नाविक समुदाय के सम्मान, कल्याण, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट रहा—समुद्र की चुनौतियों के बीच देश की सेवा करने वाले नाविकों का सम्मान, उनके प्रति कृतज्ञता और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

अस्पताल में युवक की मौत डीएम सख्त दो सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के करीब 11 दिन बाद 35 वर्षीय युवक की मौत के मामले में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी को 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच टीम परिजनों की ओर से लगाए गए इलाज में लापरवाही और अधिक रुपये वसूलने के आरोपों की भी पड़ताल करेगी। जांच कमेटी में एसडीएम सदर न्यायिक सीमा सिंह और जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. अनूप कुमार को शामिल किया गया है। टीम अस्पताल में युवक के इलाज, ऑपरेशन, दवाओं और उपचार के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। रामकोट कस्बा निवासी 35 वर्षीय शैलेश कुमार को यूरिन न होने की समस्या थी। परिजनों ने उन्हें 27 जुलाई को शहर के बस स्टॉप स्थित सेवांता अस्पताल में भर्ती कराया था। परिवार के मुताबिक, जांच के बाद डॉक्टरों ने शैलेश का ऑपरेशन किया। इसके बाद करीब 11 दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। परिजनों का आरोप है कि लगातार इलाज के बावजूद शैलेश की हालत में सुधार नहीं हुआ। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। परिवार का कहना है कि अस्पताल में इलाज पर लगातार खर्च होने के बावजूद उनकी हालत गंभीर होती गई। हालत बिगड़ी तो लखनऊ किया रेफर, रास्ते में मौत शुक्रवार रात शैलेश की हालत अचानक ज्यादा गंभीर हो गई। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन आनन-फानन में उन्हें लेकर लखनऊ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन शव लेकर वापस सेवांता अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल के गेट पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक की मां राजकुमारी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनके बेटे के इलाज में लापरवाही बरती गई। उन्होंने इलाज के नाम पर अधिक रुपये वसूलने का आरोप भी लगाया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया डीएम ने 24 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। एसडीएम सदर न्यायिक सीमा सिंह और जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. अनूप कुमार मामले की जांच करेंगे। जांच टीम परिजनों के आरोपों के साथ-साथ युवक के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन, उपचार और लखनऊ रेफर किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करेगी। डीएम ने कमेटी को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी!!

सदरपुर क्षेत्र में कृषि अधिकारी ने खाद-बीज दुकानों का किया निरीक्षण, शिकायतों पर कार्रवाई

बिसवां। सदरपुर क्षेत्र में सीतापुर के कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने खाद-बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों पर उपलब्ध खाद-बीज एवं कृषि सामग्री की स्थिति का निष्पक्ष रूप से मुआयना किया और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान कुछ किसानों ने दुकानदारों को लेकर अपनी शिकायतें भी अधिकारियों के सामने रखीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा किसी प्रकार की अनियमितता न करने की हिदायत दी। इस दौरान नबी बाबू समेत सदरपुर क्षेत्र के खाद-बीज विक्रेता एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के खाद-बीज विक्रेताओं में भी हड़कंप की स्थिति रही।

एल्पिस ग्लोबल स्कूल की अंडर-19 बालिका वॉलीबॉल टीम ने जीता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां/सीतापुर। एल्पिस ग्लोबल स्कूल के लिए यह गौरव का क्षण है। विद्यालय की अंडर-19 बालिका वॉलीबॉल टीम ने सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 जुलाई 2026 तक ग्रीन फील्ड एकेडमी, लखीमपुर खीरी में किया गया, जिसमें 32 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के दौरान एल्पिस ग्लोबल स्कूल की खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और शानदार टीमवर्क का परिचय दिया। टीम ने अपने अभियान की शुरुआत *सन इंटरनेशनल स्कूल, झांसी* को हराकर की। इसके बाद दूसरे दौर में द कैंब्रियन स्कूल, अयोध्या को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम ने मेजबान ग्रीन फील्ड एकेडमी, लखीमपुर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में फर्टिलाइजर पब्लिक स्कूल, जलालाबाद के विरुद्ध शानदार जीत दर्ज कर टीम ने फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। फाइनल मुकाबला आर्मी पब्लिक स्कूल, लखनऊ (एस.पी. मार्ग) के विरुद्ध खेला गया। कड़े और रोमांचक मुकाबले में एल्पिस की टीम उपविजेता रही और रजत पदक हासिल किया। टीम में कप्तान रुश्दा फुरकान, अमरता, माही यादव, हिबा अंसारी, जैनब फारूक, भारती यादव और ऐमन फराह शामिल रहीं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष और गर्व का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय ने कहा कि विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। एल्पिस ग्लोबल स्कूल की इस उपलब्धि ने न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों के प्रति समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया है।

हत्या के संदिग्ध मामले में कोतवाली पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। महमूदाबाद कोतवाली अंतर्गत नगर में हत्या का एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दी गयी तहरीर पर दो दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। विवश होकर मृतक के भाई को न्याय के लिए मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर गुहार लगानी पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कस्बा व थाना महमूदाबाद के मोहल्ला शहजानी निवासी कपिल गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता ने कोतवाली महमूदाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके भाई राजकुमार गुप्ता की साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। घटना 22 जुलाई 2026 की शाम लगभग 7 बजे की है, जब परिजनों को राजकुमार की मृत्यु की सूचना मिली। घटना के दिन प्रार्थी व उसके परिजन जब सरकारी अस्पताल महमूदाबाद पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि महमूदाबाद के मोहल्ला इंदौरा स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी शिवा पुत्र अज्ञात और राजकुमारी उर्फ ज्ञाना पत्नी अज्ञात मोटरसाइकिल से राजकुमार का शव लेकर आए थे। राजकुमार को देखते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जब कपिल गुप्ता ने अपने भाई राजकुमार गुप्ता की मौत के संदर्भ में शिवा और राजकुमारी से पूछताछ की, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि राजकुमार का गला कॉलोनी के एक कमरे के खिड़की में फंदे से बंधा था, जिसे वे खोलकर अस्पताल लेकर आए हैं। मृतक के भाई कपिल गुप्ता ने अपनी तहरीर में बताया कि राजकुमार गुप्ता एक सीधा-साधा मजदूर था जो पुताई का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण करता था। मृतक की पत्नी का चाल-चलन ठीक नहीं था और उसके किसी रिश्तेदार अथवा अज्ञात व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर कपिल की भाभी अपने ससुर का पैतृक घर छोड़कर इंदौरा स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने लगी थी। राजकुमार इस अवैध संबंध का लगातार विरोध करता था, जिसके चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। राजकुमार की पत्नी अक्सर राजकुमार को जान से मारने की धमकी देती थी, जिसका जिक्र मृतक ने अपने भाई कपिल और पिता से कई बार किया था। विदित हो कि 22 जुलाई 2026 को शाम करीब 7 बजे राजकुमार की संदिग्?ध परिस्थितियों में मौत इंदौरा श्थित काशीराम कालोनी में हो गयी थी। बताते है कि मौत से ठीक पहले राजकुमार ने अपनी बहन को मोबाइल पर फोन करके पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने की बात बताई थी। और डॉक्टर के शव परीक्षण में मौत का कारण 'एन्टिमोर्टम हैंगिंग' और आंखें बंद होना दर्शाया गया है। तहरीर दिए जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस द्वारा एफआईआर न दर्ज किए जाने पर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। तहरीर के मुताबिक, जब राजकुमार काम से वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। राजकुमार ने इसकी जानकारी तुरंत अपनी बहन को मोबाइल फोन के जरिए दी थी। आरोप है कि इसी रंजिश में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर किसी वस्तु से राजकुमार का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और बाद में इसे आत्महत्या दिखाने के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

झाड़ियों में मिले युवक की 12 घंटे बाद हुई पहचान, सर्विस रोड किनारे मिला था शव

सीतापुर। जनपद सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-30 की सर्विस रोड किनारे झाड़ियों में मिले युवक के शव की करीब 12 घंटे बाद पहचान हो गई। मृतक की पहचान कैमहरा गांव निवासी 35 वर्षीय निखिलेश अवस्थी उर्फ छोटू पुत्र राम प्रवेश अवस्थी के रूप में हुई है। पिता ने कपड़ों और चेहरे के आधार पर शव की पहचान की। परिजनों ने युवक की मौत को सामान्य नहीं मानते हुए अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम करीब सात बजे एनएच-30 के किनारे सर्विस रोड पर झाड़ियों में युवक का शव पड़ा मिला था।

उसकी नाक से खून निकल रहा था। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची रामकोट पुलिस ने करीब एक घंटे तक घटनास्थल की जांच की। शुरुआत में युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। उसने काले रंग की शर्ट और नीली जींस पहन रखी थी। सोशल मीडिया से पहचान कराने का प्रयास पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ शव की पहचान कराने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। स्थानीय मजदूरों ने पुलिस को बताया कि युवक शुक्रवार सुबह से आसपास के क्षेत्र में शराब के नशे में घूमता दिखाई दे रहा था।

टायर फटने से दो ट्रैकों में लगी आग नेशनल हाईवे-30 पर हुआ हादसा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे नेशनल हाईवे 30 के किनारे ले-बाई रोड पर अचानक टायर फटने से एक ट्रक की डीजल टंकी फट गई। इसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय दोनों ट्रक खाली थे और घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फायर सर्विस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात सुचारु रहा। घटना शनिवार को करीब दोपहर दो बजे थाना क्षेत्र के जमीयतपुर स्थित गप्पू मार्केट के पास मिडवे ढाबे के निकट हाईवे की ले-बाई रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार हाईवे के किनारे ट्रक ले-बाई के बराबर में दो ट्रक खड़े थे। इसी दौरान वाहन संख्या क्ष34,ञ्ञ 1171 के टायर में अचानक तेज धमाका हुआ। टायर फटने के बाद ट्रक की डीजल टंकी क्षतिग्रस्त होकर फट गई, जिससे देखते ही देखते आग भड़क उठी आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़े दूसरे ट्रक संख्या UP34 AT 2607 को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों ट्रकों में आग लगने से मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर सर्विस को दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद दोनों ट्रकों को सुरक्षित बचाया गया। राहत की बात यह रही कि दोनों वाहन खाली थे और घटना के दौरान कोई व्यक्ति ट्रक में मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। क्षतिग्रस्त ट्रक संख्या क्ष34,ञ्ञ 1171 के स्वामी रामसेवक गुप्ता निवासी गुरु नानक नगर कॉलोनी, सीतापुर बताए गए हैं, जबकि दूसरे ट्रक क्ष34,ञ्ञ 2607 के स्वामी अय्यूब खान निवासी भूसेला गोरिया, लहरपुर थाना लहरपुर बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों वाहन स्वामियों को घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और हाईवे पर आवागमन सामान्य है!!

जिम ट्रेनर की मौत, तीन युवकों पर केस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में जिम ट्रेनर रंजीत सिंह की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों से अभद्रता के आरोप और हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। शनिवार को भारतीय सिख समाज के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ओमजी, दिलीप और अनिल अवस्थी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद परिजन रंजीत सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और शनिवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार सुबह विशेषण मार्ग के पास रंजीत सिंह की बाइक हादसे का शिकार हो गई थी। वह सदरपुर स्थित जिम से ट्रेनिंग देकर बाइक से घर लौट रहे थे। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद मौके पर मौजूद तीन बाइक सवार युवकों ओमजी पुत्र अशोक कुमार, दिलीप पुत्र रमेश अवस्थी और अनिल अवस्थी पुत्र सिपाही लाल अवस्थी पर मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का आरोप था कि तीनों युवकों ने रणजीत सिंह को बाइक समेत ट्रक के सामने धक्का दे दिया। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और घटना की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। हादसे के बाद परिजनों और पुलिस चौकी बांसुरा के पुलिसकर्मियों के बीच झगड़ा हो गया था। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर पुलिस बैकफुट पर आई और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज सुबह भारतीय सिख समाज के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह समर्थकों के साथ रामपुर मथुरा थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए!

थारू विकास परियोजना को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का हब

डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने विशुनपुर विश्राम में निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

1.28 करोड़ से हो रहा परियोजना क्षेत्र का कायाकल्प, छात्र-छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण व डिप्लोमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
रमेश कुमार यादव

बलरामपुर। विकास खंड पचपेड़वा के विशुनपुर विश्राम स्थित थारू विकास परियोजना को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने थारू विकास परियोजना का विस्तृत निरीक्षण कर निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माणाधीन कंप्यूटर लैब और सिलाई-बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर लैब के माध्यम से थारू जनजाति के छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ते हुए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता संबंधी सभी औपचारिकताएं निर्माण पूरा होने से पहले ही पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र तैयार होते ही विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शुरू कराया जा सके।

हैंडलूम यूनिट से महिलाओं को मिलेगा रोजगार

डीएम ने सिलाई-बुनाई प्रशिक्षण केंद्र को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखकर इसे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने परिसर में हैंडलूम यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं स्थानीय स्तर पर हैंडलूम एवं अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर सकें।

उन्होंने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने तथा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे थारू समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार और आय के स्थायी अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

पीएचसी में संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर जोर

डीएम ने थारू विकास परियोजना परिसर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

1.28 करोड़ से संवर रही थारू विकास परियोजना

थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम के समग्र विकास के लिए शासन से ?1.28 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इस धनराशि से परियोजना क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कौशल विकास और संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। परिसर में मरम्मत, रंग-रोगन, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य भी कराए जा रहे हैं।

चित्तौड़गढ़ बंधे के सौंदर्यीकरण का भी लिया जायजा

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने चित्तौड़गढ़ बंधे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चल रहे सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें बेहतर ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता, प्रशिक्षु आईएएस श्री शिवांश जागाड़े सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

बताया गया कि पीएचसी का कायाकल्प कर आवश्यक

चिकित्सा उपकरण और अन्य संसाधन उपलध कराए गए हैं, जिसके बाद ओपीडी में मरीजों की संया में भी वृद्धि हुई है। छात्राओं से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था का लिया जायजा इसके बाद जिलाधिकारी ने राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से सीधे संवाद कर पठन-पाठन, आवासीय व्यवस्था और विद्यालय में उपलध सुविधाओं की जानकारी ली।

डीएम ने विद्यालय प्रशासन को गुणवाापूर्ण शिक्षा के साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित रूप से खेलकूद, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित कराने तथा छात्राओं को हाउसवार विभाजित कर प्रतियोगिताएं कराने को कहा, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो।

कच्चे रास्ते पर फिसली स्कूल वैन, पलटने से मची अफरातफरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नगराम,लखनऊ। कमालपुर बिचलिका-कुबहरा मार्ग से करीब 500 मीटर अंदर सोमवार को बारिश के कारण गीली हुई मिट्टी पर एक स्कूल वैन का पहिया फिसल गया। इससे वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय वैन में दो बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि दोनों बच्चे सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित वैन से बाहर निकालकर उनके घर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक, कमालपुर बिचलिका निवासी जसकरन अपनी निजी वैन संख्या यूपी32 एफए 2471 से श्री एमएल बाल विद्या मंदिर, कमालपुर बिचलिका में पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना उनके घर छोड़ने जाते हैं। सोमवार को वह तमोरिया निवासी अजीत सिंह के बच्चों ईशी सिंह (5) और रुद्र प्रताप सिंह (10) को स्कूल से लेकर घर जा रहे थे। कमालपुर बिचलिका-कुबहरा मार्ग से करीब 500 मीटर आगे कच्चे रास्ते पर बारिश के कारण मिट्टी काफी गीली थी। इसी दौरान वैन का पहिया मिट्टी में फिसल गया। चालक जब तक वाहन को नियंत्रित करता, वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। अचानक वैन पलटने से दोनों बच्चों में अफरातफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक चंद्रशेखर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों बच्चों को वैन से सुरक्षित बाहर निकलवाया। बच्चों को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। पलटी वैन को भी रास्ते से हटवाने की कार्रवाई कराई गई।

कच्चे रास्ते को दुरुस्त कराने की मांग

हादसे के बाद ग्रामीणों ने कच्चे मार्ग की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में रास्ते पर गीली मिट्टी के कारण वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।

नेक्स्टजेन आइकॉनिक इंडिया-2026 के विजेताओं ने साझा की सफलता की कहानी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 10 अगस्त सैम्म रेनेसांज़ नेक्स्टजेन आइकॉनिक मिस, मिस्टर एवं मिसेज इंडिया 2026 की सफलता के बाद सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं, प्रथम एवं द्वितीय उपविजेताओं तथा प्रतिभागियों ने मीडिया से संवाद कर अपने संघर्ष, अनुभव, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। प्रेस वार्ता में लखनऊ की वंशिका, मुंबई के देवांश तिवारी, आगरा की इति और देहरादून की ज्योति धाकरे सहित विभिन्न श्रेणियों के विजेता एवं उपविजेता मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने बताया कि प्रतियोगिता का सफर उनके लिए केवल खिताब हासिल करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने, व्यक्तित्व विकास करने और अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अनुभव मिला। सैम्म रेनेसांज़ की आयोजक एवं संस्थापक सौम्या साहू ने कहा कि नेक्स्टजेन आइकॉनिक मिस, मिस्टर एवं मिसेज इंडिया का उद्देश्य प्रतिभाओं को केवल खिताब प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकें। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी प्रतिभा, ऊर्जा और नए विचारों से भरपूर है। आवश्यकता है कि उन्हें सही मंच, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले। सैम्म रेनेसांज़ आगे भी प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर प्रदान करने और उन्हें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। विजेताओं ने माना खिताब के साथ बढ़ी जिम्मेदारी विजेता वंशिका, देवांश तिवारी, इति और ज्योति धाकरे ने कहा कि नेक्स्टजेन आइकॉनिक इंडिया की यात्रा उनके लिए सीख, अनुभव और आत्मविश्वास से भरी रही। इस मंच ने उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने के साथ स्वयं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विजेताओं ने अपने खिताब को नई जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वे भविष्य में अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के साथ-साथ नई प्रतिभाओं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं ने हासिल किए खिताब मिस इंडिया वर्ग में लखनऊ की वंशिका ने नेक्स्टजेन आइकॉनिक मिस इंडिया 2026 का विजेता खिताब हासिल किया। हैदरगढ़ की यशस्विनी प्रथम उपविजेता और ओडिशा की तृषा द्वितीय उपविजेता रहीं। मिस्टर इंडिया वर्ग में मुंबई के देवांश तिवारी ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु के अनिवार्य जैन प्रथम उपविजेता और जयपुर के समर नगर द्वितीय उपविजेता रहे। मिसेज इंडिया वर्ग में आगरा की इति विजेता बनीं। लखनऊ की सरवजीत कौर प्रथम उपविजेता और लखनऊ की दीपा द्वितीय उपविजेता रहीं। वहीं, देहरादून की ज्योति धाकरे ने नेक्स्टजेन आइकॉनिक मिसेज एलीट इंडिया 2026 का विजेता खिताब हासिल किया। अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रभावशाली प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने प्रतियोगिता में अलग पहचान बनाई। आगामी आयोजनों को मिलेगी नई दिशा आयोजकों के अनुसार इस आयोजन की शो निदेशक इशिता रस्तोगी रहीं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता और अनुभव से आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगामी रेनेसांज़ आयोजनों की जिम्मेदारी शो निदेशक मोनिका भदौरिया संभालेंगी। आयोजकों ने बताया कि आगामी आयोजनों में एसएनए लग्जरी मेकओवर्स बाय नेहल सौंदर्य प्रसाधन एवं श्रृंगार सहयोगी के रूप में विशेष सहयोग देगा। आयोजकों का कहना है कि मोनिका भदौरिया और एसएनए लग्जरी मेकओवर्स बाय नेहल की विशेषज्ञता एवं रचनात्मकता से आने वाले आयोजन और अधिक भव्य, आकर्षक एवं शानदार बनाए जाएंगे।

भवरेश्वर धाम में गूंजा हर-हर महादेव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

निगोहां। श्रावण मास के पावन अवसर पर प्राचीन भवरेश्वर धाम में शुक्ला परिवार की ओर से 16वां वार्षिक विशाल भंडारा आयोजित किया गया। रविवार रात से शुरू हुआ भंडारा सोमवार शाम करीब पांच बजे तक निरंतर चलता रहा। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं, राहगीरों और शिवभक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। बाबा भवरेश्वर के दर्शन-पूजन के बाद भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच आयोजन समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे रहे। भंडारे के दौरान हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा धाम शिवमय नजर आया। श्रद्धालुओं ने बाबा भवरेश्वर के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं की सेवा को भगवान शिव की सेवा मानकर पूरे मनोयोग से प्रसाद वितरण और अन्य व्यवस्थाएं संभालीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत मोहनलालगंज प्रतिनिधि डॉ. अजय पांडेय, सत्यम भैया, ग्राम प्रधान दयालपुर प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार पाल तथा ग्राम प्रधान भद्दी शीर्ष सुरेश कुमार समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग पहुंचे। अतिथियों ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजन की सराहना की और समिति के सदस्यों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। आयोजक शैलेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में हुए भंडारे में सतीश शुक्ला, रजनीश शुक्ला, हर्ष शुक्ला, नितिन शुक्ला, मयंक शुक्ला, विवेक तिवारी, भोला शुक्ला, छोटू शुक्ला, सुरेश गोयल, वीरेंद्र जायसवाल, संजय अग्रवाल, गौरव सिंह, विशाल तिवारी, पवन कुमार, पप्पू देवता, कश्यप, रुपेश, प्रेम शर्मा समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे। शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि श्रावण मास में बाबा भवरेश्वर धाम में भंडारा आयोजित करना शुक्ला परिवार के लिए आस्था और सेवा का विषय है। लगातार 16वें वर्ष आयोजित भंडारा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा भवरेश्वर की कृपा से भविष्य में भी यह धार्मिक एवं सेवा कार्य जारी रहेगा।

कृमि मुक्ति दिवस पर 473 बच्चों ने खाई एल्बेंडाजोल की दवा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बच्चों को पेट के कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा खिलाई गई। शिक्षकों ने बच्चों को दवा के महत्व और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक किया। प्राथमिक विद्यालय गुमानीखेड़ा में प्रधानाध्यापक अनिल कुमार वर्मा की देखरेख में 59 छात्र-छात्राओं को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। उन्होंने बच्चों को बताया कि पेट में होने वाले कृमि उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कृमिनाशक दवा के सेवन से कृमि संक्रमण से बचाव के साथ कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलती है। विद्यालय में बच्चों को कतारबद्ध कर व्यवस्थित तरीके से दवा खिलाई गई। कार्यक्रम में सहायक अध्यापिकाओं वंदना यादव, राम कुमारी और ज्योति पटेल ने सहयोग किया। शिक्षकों ने बच्चों को दवा सेवन से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी दी। इसी क्रम में बेसिक विद्यालय करोरा में 311, प्राथमिक विद्यालय करोरा-2 में 58 और प्राथमिक विद्यालय अचलीखेड़ा में 45 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। इस प्रकार चारों विद्यालयों में कुल 473 बच्चों ने कृमिनाशक दवा का सेवन किया। शिक्षकों ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले अभियानों में सहयोग करें। ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी विद्यालयों में आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।

एसडीएम ने कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत इक्कोतरनाथ मंदिर एवं धनारा घाट पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पूरनपुर (पीलीभीत)। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी पूरनपुर मयंक गोस्वामी एवं आशीष कुमार गुप्ता, तहसीलदार पूरनपुर द्वारा इक्कोतरनाथ मंदिर एवं धनारा घाट पर पहुंचकर कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया।इस दौरान नायब तहसीलदार भी मौके पर उपस्थित रहे। उपजिलाधिकारीमयंक गोस्वामी के द्वारा कावड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई तथा सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को अपने निर्धारित ड्यूटी स्थलों पर समय से उपस्थित रहकर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक निगरानी एवं समुचित व्यवस्थाओं के बीच कांवड़ यात्रियों को समय से रवाना कराया गया। यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, आवागमन एवं श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। तहसील प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्ण सतर्कता एवं आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

निबंधन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार बदलाव के विरोध में पांचवें दिन भी धरना

.....मोहनलालगंज तहसील के विभिन्न कार्यालयों में अधिवताओं ने की तालाबंदी, एआईजी निबंधन ने वार्ता कर शासन तक मांग पहुंचाने का दिया आश्वासन।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। उत्तर प्रदेश शासन के स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग की ओर से जारी चार अगस्त की अधिसूचना के विरोध में मोहनलालगंज तहसील में अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों में तालाबंदी कर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिसूचना लागू होने से मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र की संपत्तियों के निबंधन के लिए लोगों को लखनऊ के अलग-अलग उपनिबंधक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। धरना स्थल पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वितीय लखनऊ रमेश चन्द पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता की। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याएं और आपत्तियां सुनीं। साथ ही उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि, वार्ता के बाद भी अधिवक्ताओं ने अधिसूचना वापस होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि निबंधन क्षेत्राधिकार में बदलाव से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय और धन दोनों की अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ेगी। उनका यह भी दावा है कि क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन होने से भविष्य में संपत्ति संबंधी जालसाजी की आशंका बढ़ सकती है।

किसान संगठन ने दिया नैतिक समर्थन

मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के आंदोलन को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भी नैतिक समर्थन दिया है। संगठन के प्रदेश महासचिव दिनेश यादव ने बार एसोसिएशन को भेजे पत्र में शासन की चार अगस्त की अधिसूचना वापस लेने की मांग का समर्थन किया। पत्र में कहा गया कि निबंधन व्यवस्था में बदलाव से आम जनता को परेशानी होगी और यह जनहित में नहीं है।

दो उपनिबंधक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका

वहीं, सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वितीय की ओर से महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र में मोहनलालगंज उपनिबंधक कार्यालय के क्षेत्राधिकार को विभक्त कर दो उपनिबंधक कार्यालय खोले जाने के पूर्व प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। पत्र के अनुसार इस संबंध में समिति गठित कर प्रस्ताव तैयार किया गया था। प्रस्ताव को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबंधक लखनऊ तथा जिलाधिकारी लखनऊ के अनुमोदन के बाद शासन स्तर पर भेजा जा चुका है। धरने में बार के पूर्व महामंत्री ललित मिश्रा, अधिवक्ता वैभव द्विवेदी, विनय मिश्रा, देवेश सिंह, विष्णु प्रताप सिंह (पुनपुन), विपिन कुमार पाल,अंकित यादव, सिराज खान, अजय यादव मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।